

विचार बिन्दु

कुछ प्रलोभन परिश्रमी व्यक्ति को हो सकते हैं, किंतु सारे प्रलोभन तो केवल आलसी व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हैं। -मुक्ता

गिग वर्कर्स - समस्याएं और चुनौतियां

ग) वर्कर्स शब्द वैसे तो 1952 से ही विशेष में प्रचलन में है, किंतु भारत में इसकी चर्चा हाल के वर्षों में ही सांघ हुई है। यह शब्द उन व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है जिनका नियोजन के द्वारा कामचोरों वाला रिश्ता नहीं होता। यह बिल्कुल अल्प अवधि के लिए विशेष काम करने वालों पर लागू होता है। इनकी कार्य अवधि में बहुत लचीलापन संभव है और कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार इस काम को कर सकता है, जिसके लिए निर्धारित पारिश्रमिक देय होता है।

भारत के परिप्रेष्य में यह शब्द दो प्रकार के कार्मा के लिए सर्वाधिक प्रचलन में है पहला, उबर - ओला टैक्सी कंपनियों के वाहन चालकों के लिए और दूसरा विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉयस के लिए। कुछ लोग इस काम को अपने मुख्य काम के अलावा अतिरिक्त कमाई के लिए करते हैं, तो अधिकांश के लिए यही एकमात्र रोजगार है।

चूँकि इस प्रकार के काम में लगे लोगों का नियोक्ता के साथ सेवा संबंधी कोई पूर्णकालिक समझौता नहीं है, इन पर श्रम कानून के कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

यह सही है कि भारत में लगभग 85 प्रतिशत श्रमिक और कर्मचारी असंतुष्ट क्षेत्र में हैं अर्थात् ये संगठित होकर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसी का लाभ उठाकर नियोजता सामान्यान्वयत कर्मचारियों को जब चाहे दबा देते हैं। उन्हें किसी प्रकार की सेवा सुरक्षा और सेवा संबंधी अन्य लाभ भी सामान्यतः नहीं मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में से अधिकांश किसी एजेंसी के माध्यम से सविदा पर काम करते हैं, जिनका नियोजकों के साथ सीधा संबंध नहीं होता। यही नहीं, अब तो सरकार ने भी अपने अधिकांश कर्मचारी किसी एजेंसी के माध्यम से सविदा पर रखे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के सरकारी सेवा नियमों के लाभ से वंचित रहते हैं।

एट्कीस के क्षेत्र में जब से उबर और ओला कंपनियाँ ने प्रवेश किया, तब से एट्कीस संचालन का स्वरूप ही बदल गया। यह बड़े रोजगार के अवसर के रूप में देखा गया। कई बेरोजगार युवाओं ने प्रैंक कार्टी खरीद कर अपने आया को उबर और ओला के साथ पंजीकृत करवा लिया। प्रारंभ में उन्हें कई प्रकार के इंसेंटिव दिए जाते थे जो, 'राइड्स' की संख्या पर आधारित थे। ग्राहकों को भी कई प्रकार की छूट दी जाती थी। अच्छी कमाई के लालच में कई लोगों ने ऋण लेकर कार्टी खरीदी और एट्कीस के रूप में इन कंपनियों के साथ रिस्कर करवा दी। शुरू में उनसे कमाई भी ठीक-ठाक हो जाती थी इसलिए यह स्न रोजगार का अच्छा माध्यम बन गया। जैसे-जैसे ग्राहकों की निम्नता इन कंपनियों पर बढ़ती गई ऐसे-सेसे उबर और ओला में रजिस्टर्ड वाहनों को दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती प्रारंभ कर दी एवं उनका कमीशन कटार कर ड्राइवरों को मिलने वाली राशि भी कम हो गई। कई लोग तो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गए कि उनकी कमाई में से कार लोन की किस्त चुकाना भी मुश्किल ही गया। उसमें से कमाई होगा तो दूर की बात थी। लोन की किश्तें नहीं चुका पाने के कारण लोन देने वाली कंपनियों बीच रास्ते से ही बाधन बढ़ाकर रस्ती उठा कर ले जाते लगीं। उनका ससेसे बड़ी समस्या यही थी कि ये कभी संगठित होकर इन बड़े कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सके। जैसे भी ये कंपनियों इतनी बड़ी हैं कि इनके लिए किसी भी यूनिन को तोड़ना और उसके नेताओं को खरीदना कठिन काम नहीं है। यही एक कारण है, जिससे संगठित होकर उबर और ओला कंपनियों के साथ, ड्राइवरों का कोई समानांतर समझौता नहीं हो पाया।

टाँकसी के अतिरिक्त, दूसरा जो बड़ा असर योगेगारों के लिए उपलब्ध हुआ है वह प्लेटफार्म बेकड सेवा प्रदाता जैसे किगो, जोमेटो, बिलकंडल आदि माध्यम से सामान लोगों के घरो तक पहुंचाने का है। इस प्रकार के सामग्री में लगे लोगों को 'डिलीवरी बायज' कहा जा सकता है। आप किसी भी शहर को छहक पर किसी भी समय निकल जाएं तो सड़क पर आपको बहुत बड़ा सा बॉक्स मोटरसाइकिल पर पीछे ठेके हुए ट्रेने से मोटरसाइकिल चलाते हुए युवा दिखें जायेंगे। इनके टी शर्ट पर लिखे नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि यह सब डिलीवरी बायज है। इनमें कई ऐसे हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और अपने लिए अतिरिक्त आय के सधन के रूप में यह काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए योगेगार का यही एकेमात्र अवसर है।

विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक हो गई है कि बिल्किट जैसी कंपनी ने तो ठाकौरों तक 10 मिनट में सामान पहुंचाने का गारंटी देना प्रारंभ कर दिया। इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया। इस समय-सीमा में सामान पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल चलाने वाले बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हैं। कई बार ट्रैफिक लाइट का भी उल्लंघन करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। न इनके काम के घंटे निश्चित हैं। ये जब भी इस कंपनी में 'लाग इन' कर लेते हैं तो कंपनी का आदेश मिलने की उनके पालन के लिए उल्लंघन

भारत में प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स की संख्या जो 2020-21 में लगभग 77 लाख थी वह 2024-25 में बढ़कर लगभग ढाई करोड़ हो गई है। इस संख्या में इतनी वृद्धि, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति का ही सूचक है। कई डिलीवरी बॉयज़ से बात करने पर पता लगा कि उनमें से कई स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। वे अपने स्कूल के दिनों में ही काम करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ लोग इन करने के बाद भी ये डिलीवरी का आदेश लेने से मना कर देते हैं। उन्हें एक या दो दिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और इन्हें उस कंपनी द्वारा कोई काम नहीं दिया जाता।

डिलीवरी बॉयज़ की समस्या को नजदीकी से देखने और अनुभव करने के लिए एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने स्वयं डिलीवरी बॉय के रूप में तीन दिन स्वयं को, जोमेटी और ब्लिंकित के लिए काम किया।

का जोखिम भरा कार्य, नाम मात्र की आमदनी में करने के लिए मजबूर है। यह लेख लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अब जब भी पाठक किसी डिलीवरी बॉय को सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देखें, तो उनकी अत्यंत कठिन कार्य परिस्थितियों का उनको ध्यान रहे ताकि वे उनके प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें।

10 से 15 किलो तक वजन उठाकर पहुंचना पड़ा। निरंतर इस प्रकार का काम करते रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तियों को दिलीवरी की गई, उनमें से किसी ने मुस्कुरा कर दिलीवरी बाँच को धन्यवाद तक नहीं कहा, टिप तो दूर की बात है। पाठकों से यह आग्रह है कि भविष्य में उनके पास यदि कोई दिलीवरी बाँच आए तो उसको सहारा करे एवं उसको मुस्कुरा कर धन्यवाद अवश्य दें। इससे यदि उसे आर्थिक लाभ न भी हो तो उसे अच्छा एहसास तो होगा।

अधिक कमाई के लालच में ये दिलीवरी बाँच कब बारा 10-12-15 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इस प्रकार के काम से थकाान आस्थाविकर के बयोंकि शारीरिक क्षमता भी सीमित होती है। इस कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ जाती है। क्योंकि इस प्रकार के काम करने वाले लोग बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए इसमें संगठित होकर अपना पारिश्रमिक बढवाने के लिए आंदोलन कर पाना संभव नहीं है। यह वास्तविकता, देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति का एक संकेत मात्र है। इसी लिए उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार को पत्रकारों से अपेक्षा है।

राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जिसने राजस्थान प्लेटफार्म ब्रेड गिंग वर्कर्स (पंजीयन एवं कल्याण) अधिनियम, 2023 बनाया। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्लेटफार्म ब्रेड वर्कर के लिए पंजीयन की अनिवार्यता है। इसी प्रकार, सेवा प्रदाता को भी अपना पंजीकरण करना होता है। इनके लिए स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना बीमा आदि की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अंतर्गत एक गिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन और वेलफेयर फंड का प्रावधान किया गया है। इस कल्याण कोष के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गिंग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना के संभय सहायता करने की व्यवस्था की गई है। श्रम मंत्राली की अध्यक्षता में यह बोर्ड बनाया गया है। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव सदस्य हैं।

राजस्थान द्वारा यह कानून बनाए जाते के बाद कर्नाटक और केरल ने भी इसी प्रकार के कानून बनाए हैं। यह कानून बहुत आवश्यक था क्योंकि इसकें अभाव में लोग वर्कर्स को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था। यदि यह कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाए और सेवा प्रदाता थोड़ी सी संवेदनशीलता का परिचय दें तो इन लोग वर्कर्स को सेवा शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि इन पर कोई न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होता, किंतु समग्र के साथ-साथ संगठन बनने के बाद, संभव है इनके लिए न्यूनतम आय प्रति घंटा निर्धारित की जा सके।

भारत में प्लेटफार्म वेस्ट गिंग वर्कर्स की संख्या जो 2020-21 में लगभग 77 लाख थी वह 2024-25 में बढ़कर लगभग ढाई करोड़ हो गई है। इस संख्या में इतनी वृद्धि, बेरोजगारी की गंभीर स्थिति का ही सूचक है। कई डिलीवरी वॉयज से बात करने पर पता लगा कि उनमें से कई स्त्राकर और किसी अन्य नौकरी के अभाव में इस प्रकार का जोखिम भरा कार्य, नाम मात्र की आमदनी में करने के लिए मजबूर हैं।

यह लेख लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अब जब भी पाठक किसी डिलीवरी बाॅय को सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए देखें, तो उनकी अत्यंत कठिन कार्य परिस्थितियों का उनको ध्यान रहे ताकि वे उनके प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें।

10 मिनट में डिलीवरी करने की गारंटी देने के विज्ञापन पर हाल ही में न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है क्योंकि इसी गारंटी के कारण पेनल्टी से बचने के लिए डिलीवरी करने वाले तेज गति से मोटर साइकिल चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना भी करते हैं ताकि किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगे।

गिंग वकस के कारण नागरिकों के कई प्रकार के काम समय पर घर बैठ होने लगें हैं और वह घर बैठकर किसी भी प्रकार का सामान तय्यार प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि इस काम में लगे लोगों का सप्ताह शर्तें, सुल्का और कल्याण के लिए बनाए गए कानून के प्रावधानों का पालन उसकी भावना के अनुसार किया जाए ताकि यह वर्ग हर प्रकार के शोषण से बच सके।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)